>

Title: Need to streamline the process of toll tax collection with regard to the construction of various roads in the country.

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): माननीय सभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से सबसे ज्यादा पैसा सड़कों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से लगभग सात लाख करोड़ रूपए का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था कि इतनी कीमतों की सड़कें बनेंगी। पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो सड़कें हमारे देश में बन रही हैं वे टोल-टैक्स के आधार पर बन रही हैं। टोल-प्लजा के आधार पर जो सड़कें बनती हैं, उन सड़कों का प्रभाव सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। निश्चित तौर से उससे अवैध वसूली के उपाय बनते हैं। यह रिश्वतखोरी और मँहगाई का भी कारण बनती है। जितने मालवाहक उस टोल सड़क से गुजरते हैं, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में टोल-टैक्स देना पड़ता है। मैं एक-दो जगह का उदाहरण देना चाहता हूँ। जहां पर उन कम्पनियों ने बीओटी रोड बनाए हैं वहाँ उन्होंने 90 प्रतिशत रिटर्न पाया। आज सदन में दैनिक भास्कर और तमाम अखबार को लेकर चर्चा होती रही। पक्ष और विपक्ष दोनों ने कहा। मैं उसी संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। इसी अखबार में एक खबर छपी कि लगाए पाँच सौ करोड़ रूपए और कमाए चार हजार करोड़ रूपए। इस सरकार की नीतियों का खमियाजा कहीं न कहीं हमारी देश की जनता भुगत रही है। सूरत से भरूच चार लेन की एक सड़क पहले से निर्मित थी। उसको छह लेन में परिवर्तित करने की बात कही गई। आईआरडी कम्पनी को ठेका दे दिया गया। उसने 504 करोड़ रूपए सरकार को चुकता कर उस सड़का का ठेका ले लिया। प्रत्येक वर्ष लगभग 128 करोड़ रूपए की वसूली की, क्योंकि सालाना दस प्रतिशत की वृद्धि पर उसे ठेका दिया गया था। लगभग 1600 करोड़ रूपए की आमदनी उस सड़क से दस साल में हो जाएगी। ग्यारह सौ करोड़ रूपए की कमाई है। इसी के ऐवज में एक पार्ट सूरत से दैसर तक बनना था। उसी पार्ट को बगैर पैसा चुकता किए इसी कम्पनी को दोबारा दे दिया गया। मैं इस बात को इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ क्योंकि देश की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। बार-बार सरकार की तरफ से वक्तव्य आता है कि मँहगाई को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। मँहगाई बढ़ने के यही सब कारण हैं। जनता का पैसा लुटा के आप निजि कम्पनियों और व्यापारियों की जेब में भरते जा रहे हैं। सूरत से भरूच चार लेन की एक सड़क थी। उस सड़क को छह लेन का करने के लिए उसका भी ठेका दिया गया। जिस दिन वह सड़क दी गई वहां पर काम शुरू होने से पहले उस कम्पनी को अधिकार दे दिया गया कि आप टोल-टैक्स एकत्रित कर लीजिए। यह अखबार की खबर है। इसी सड़क का अगला हिस्सा सूरत से दैसर तक का ठेका उसी कम्पनी को मिला। लेकिन इस बार ठेके की शर्त बदल गई। इस बार कम्पनी ने सरकार को कोई भुगतान नहीं किया। क्योंकि इस पर काम खत्म करने के बाद नहीं बल्कि काम शुरु करने के पहले दिन टोल वसूली का अधिकार मिल गया है। यहां के 4 टोल प्लाजा से उसे एक करोड़ रुपये प्रतिदिन की आमदनी है। टोल का 38 प्रतिशत भाग सरकार को देना है टोल शेयरिंग के रुप में। लेकिन काम खत्म होने के बाद ही सरकार को दिया जायेगा, तब तक सब ठेकेदार का है। ढाई साल में 1100 करोड़ की आमदनी है जबकि खर्चा होना है 1600 करोड़ रुपया। इसकी वसूली अगले नौ साल और होगी, कम्पनी 500 करोड़ रुपये खर्च करके लगभग 4000 करोड़ रुपया कमायेगी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री धनंजय सिंह : सभापति महोदय, मेरा कहना है कि हमारे देश में टोल टैक्स की जो प्रवृत्ति है, इसके बजाय जो हमारी सरकार सड़कों का निर्माण कर रही है, उसे हम ब्रेक करके प्राइवेट लोगों को बढ़ाकर जनता की जेब पर न डालें। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।